भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2723

जिसका उत्तर 17 मार्च, 2022 को दिया जाना है।

.....

जलभराव क्षेत्रों का सर्वेक्षण

2723. श्री अशोक कुमार यादवः

क्या ***जल शक्ति* मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बिहार सहित राज्यों में जलभराव क्षेत्रों का कोई सर्वेक्षण किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और मधुबनी और दरभंगा जिलों में ऐसे कितने क्षेत्र हैं;

(ख) क्या सरकार ने उक्त जिलों के चिन्हित क्षेत्रों में जलभराव की समस्या के स्थायी समाधान हेतु कोई योजना बनाई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान सरकार द्वारा इस संबंध में कितनी निधि स्वीकृत और उपयोग की गई है;

(घ) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई लक्ष्य निर्धारित किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा उक्त लक्ष्यों को यताशीघ्र प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री (श्री बिश्वेश्वर टुडू)

कः वर्ष 2003-2008 के दौरान, इस मंत्रालय के तहत केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) द्वारा देश में सभी वृहत और मध्यम सिंचाई (एमएमआई) परियोजनाओं के कमांड क्षेत्र में जलभराव और अलकलाइन प्रभावित मृदा स्तर के मूल्यांकन के लिए एक अध्ययन किया गया था। यह अध्ययन क्षेत्रीय रिमोट सेंसिंग सेवा केंद्र इसरो जोधपुर द्वारा किया गया, जिसमें 88,896 हजार हेक्टेयर कमांड क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए कुल 1701 परियोजनाओं को शामिल किया गया। इस अध्ययन में देश में कुल 1,719 हजार हेक्टेयर भूमि होना मूल्यांकित किया गया।

इस अध्ययन में 5,939 हजार हेक्टेयर के कमांड क्षेत्र को शामिल करते हुए, बिहार में 132 वृहत और मध्यम सिंचाई परियोजनाएं भी शामिल की गईं। इस अध्ययन के अनुसार, बिहार में जलभराव क्षेत्र मधुबनी जिले में 11.49 हजार हेक्टेयर और दरभंगा जिले में 20.25 हजार हेक्टेयर सहित कुल 628 हजार हेक्टेयर में निर्धारित किया गया था।

(ख) से (ङ): जैसा कि बिहार सरकार द्वारा सूचित किया है कि दरभंगा और मधुबनी जिलों में जलभराव की समस्या का स्थायी समाधान खोजने के लिए बिहार सरकार द्वारा आगामी वित्तीय वर्ष 2022-23 में इन जिलों के जलभराव का एक विस्तृत पर्यवेक्षण कराना प्रस्तावित किया गया है। इस संबंध में, दरभंगा जिले के कुशेश्वर अस्थान ब्लॉक में 400 वर्ग कि.मी. के पर्यवेक्षण के लिए पहले ही एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आमंत्रित किया जा चुका है। दो जिलों के शेष क्षेत्रों के लिए भी ऐसी दो कार्यवाही यथाशीघ्र करना प्रस्तावित किया जाएगा।

*****